अंतरराष्ट्रीय संबंध परिषद में प्रधानमंत्री का भाषण

24 सितंबर, 2004

न्यूयार्क

डॉ.हास, डॉ.बोलिंगर, प्रो.फ्रैंकेल, डॉ.देसाई एवं उपस्थित सज्जनो,

आज मुझे यह अवसर मिला है कि मैं भारत एवं अमरीका के बीच आने वाले वर्षों में मजबूत एवं परस्पर बढ़ती हुई भागीदारी की संभावनाओं के बारे में अपने विचार आपके समक्ष प्रस्तुत करूं ।

दोनों देशों के जीवन-मूल्यों एवं इनके नियंता कारकों की समानता के कारण आज विश्व परिदृश्य एक ही हो गया है ।

भारत-अमरीका के संबंधों पर भाषण देने वाले वक्ताओं का इस बात पर जोर देना स्वाभाविक है कि ये दोनों ही देश लोकतांत्रिक हैं और यह अनिवार्य रूप से हमारे दोनों देशों के बीच मानव-मूल्यों को समानता प्रदान करता है जो स्वाभाविक रूप से मजबूत सहभागिता की दिशा में कदम होना चाहिए । मेरा विश्वास है कि यह दृष्टिकोण सही है । मूलतः लोकतांत्रिक समाज के प्रति जो कि खुला, उदार एवं सहिष्णु समाज भी है, हमारी प्रतिबद्धता हमारे बीच समान मूल्यों के आधार की परिचायक है जो बहुत महत्वपूर्ण है । किन्तु हमें वास्तविकता के आधार पर यह भी देखना चाहिए केवल इसी से हमारे बीच निकट संबंधों को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है और न ही उसकी

गारंटी दी जा सकती है क्योंकि यह बात इस बात की गवाह है कि भारत-अमरीका संबंधों में पहले काफी उतार- चढ़ाव आते रहे हैं ।

वास्तविक सहभागिता के लिए केवल लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता की ही जरूरत नहीं होती है, वास्तविक सहभागिता के लिए मानव मूल्यों की समानता की भी जरूरत होती है जिसके पीछे आपसी हितों को एकरूप करने व विश्व परिदृश्य को अपनाने की भावना हो । मैं मानता हूं कि पिछले 15 वर्षों से या उससे अधिक समय में विश्व में जो कुछ भी घटित हुआ उससे हमारी आपसी निकटता और जागरूकता इतनी बढ़ी जितनी पहले कभी नहीं थी । मेरे विचार में विश्व परिदृश्य की पुनर्व्याख्या करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में कम से कम तीन प्रमुख कारकों ने अपनी भूमिका निभाई है ।

सबसे पहला कारक है शीत युद्ध का अंत । पुराने खतरे दूर हुए और नए-नए खतरे उभर कर सामने आए । दिल्ली, वाशिंगटन एवं अन्य देशों की राजधानियों में भी नीतिगत समीकरणों का पुनर्मूल्यांकन किया गया । दूसरा कारक है भूमंडलीकरण की गति का बढ़ना । इसका विकासशील देशों और विशेष रूप से भारत की आर्थिक नीति पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा । तीसरा, बड़ी संख्या में लगभग 2 मिलियन भारतीय अमरीकी समुदाय वर्षों से अमरीका में रह रहा है । उन्होंने अमरीका की मुख्य धारा में पूर्णतः शामिल होते हुए इस देश में अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति को दर्ज किया है । उन्होंने मजबूत द्विपक्षीय संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के लिए अपनी आवाज उठाई है। मेरा विश्वास है कि इन तीन कारकों ने दोनों देशों के बीच सहभागिता पर आधारित त्वरित समन्वय के भविष्य को रेखांकित किया है ।

भारत के लिए हमारी लोकतांत्रिक राजव्यवस्था तथा बहुवाद एवं उदारतावाद के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और इन कारकों के प्रति हमारा रुख हमारे लोकतांत्रिक ढांचे से और बहुवाद एवं उदारतावाद के गहरे जीवन मूल्यों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता से बहुत अधिक प्रभावित हुआ है । अब मैं इसके बारे में विस्तार से कहना चाहूंगा ।

दूसरे विकासशील देशों की तरह हमारी भी मुख्य चुनौती आर्थिक विकास की है। हम अपनी जनता के जीवन स्तर को सुधारने के प्रति कटिबद्ध हैं और यह तभी हो सकता है जब हम यथाशीघ्र अपनी अर्थव्यवस्था को आधुनिक, मध्यम आय अर्थव्यवस्था में रूपांतरित कर दें । तथापि हमने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संसदीय लोकतंत्र के ढांचे के भीतर कार्य करने का मार्ग अपनाया है । हमने संसदीय लोकतंत्र व्यवस्था को विश्वव्यापी स्वीकृति और भारत की आजादी के समय औद्योगिक रूप से विकसित देशों की आय की तुलना में न के बराबर थी और साक्षरता दर के आधार पर जो केवल 18% थी, अपनाया है ।

आर्थिक विकास का कार्य कभी भी आसान नहीं रहा है, यह उस समय और भी अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है जब यह महसूस किया जा रहा हो कि लोकतंत्र निम्न आय के वातावरण में कार्य कर रहा है । आर्थिक परिवर्तन के लिए बहुत कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं जिनमें प्रायः दीर्धकालिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अल्पकालिक लक्ष्यों का बलिदान देना पड़ता है । राजनीति का दबाव हमेशा ही दूरदृष्टि का बोझ नहीं उठा सकता । कई पर्यवेक्षकों को इस पर संदेह है कि क्या लोकतांत्रिक भारत इस क्षेत्र में बेहतर परिणाम दे सकेगा और ऐसा भी वक्त आया है जब हमारा कार्य-निष्पादन अपेक्षित स्तर से काफी कम रहा । फिर भी कुल मिलाकर हमें अपनी उपलब्धियों पर गर्व है ।

आज हमारी ऐसी अर्थव्यवस्था हो गई है जो कि लगभग 6% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है । 20 वर्षों में, आज हम बिजली की खरीद की दृष्टि से विश्व में सकल घरेलू उत्पाद वाले चौथे सबसे बड़ा देश बन गए हैं । हमारे पास विश्वस्त, प्रतिस्पर्धी निजी क्षेत्र है जो कि उत्कृष्ट उद्यमशीलता को प्रदर्शित करता है । भारत के पास उच्च कोटि के मानव संसाधन हैं और इसका कानून एवं वाणिज्यिक लेखाकरण संबंधी आधारिक ढांचा आधुनिक व्यवसाय के अनुरूप है । हमारी अर्थव्यवस्था ने उन्नत प्रौद्योगिकी के कई क्षेत्रों में काफी प्रगति की है ।

यह पिछले 50 वर्षों के दौरान ऐसी संस्थाओं के निर्माण के लिए किए गए सतत प्रयासों का फल है जिन्होंने दीर्घकालिक आर्थिक विकास की नींव प्रदान की । ये सब जवाहर लाल नेहरू की दूरदृष्टि का ही नतीजा था । यह उन आर्थिक सुधारों का भी परिणाम है जिसने हाल के वर्षों में हमारी प्रतिस्पर्धा को बहुत अधिक बढ़ाया है । आज आर्थिक विश्लेषक इस बात से सहमत हैं कि भारत एक निश्चित अवधि में 8% की वृद्धि दर प्राप्त कर सकता है । सच्चाई यह है कि यह उपलब्धि हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधार पर तैयार की गई और लागू की गई है । यह एक ऐसी उपलब्धि है जिस पर सभी भारतीयों को गर्व है ।

लोकतंत्र में चुनाव अनिवार्य तत्व होता है । हमें अपने मतदाताओं के निष्पक्ष मतदान और उनके द्वारा प्रतिनिधियों का चुनाव किए जाने पर गर्व है । अमरीका पूरे विश्व में लोकतांत्रिक मूल्यों के संवर्धन के लिए सहायता देने का इच्छुक है ।

विकासशील देशों में लोकतांत्रिक संस्थाएं कैसे उन्नति करती हैं या यों कहें कि विकासात्मक लक्ष्यों को कैसे प्राप्त करती हैं, भारत इसका जीता-जागता उदाहरण है ।

लोकतंत्र के प्रति हमारी प्रतिबद्धता बहुवाद एवं उदारतावाद के गहन मूल्यों के प्रति वचनबद्धता से जुड़ी हुई है । भारत ने जिस विविधता को अंगीकार किया है वह हमारे लोकतंत्र का महत्वपूर्ण अंग है, आज जिसे बहु संस्कृतिवाद कहा जा रहा है उसकी जड़ें हमारी संस्कृति में बहुत गहरे तक जमी हुई हैं । आधुनिक राज्य बनाने की प्रक्रिया में इसे संरक्षित रखे जाने के लिए व्यापक स्तर पर सामाजिक राजनीतिक प्रयोग करना होगा । इसकी सफलता से हमारे आधारभूत दर्शन की पुष्टि होगी । यह लोकतांत्रिक प्रकिया का एक ऐसा मॉडल है जिसका आज के इस विभाजित समाज में काफी महत्व है जिसमें हम किसी की जाति या भाषा या धर्म या राष्ट्रीयता के बारे में काफी उत्तेजक भाषा का प्रयोग करने के बारे में सुनते हैं । इस तरह दो समाजों के बीच में दरार डालने वाली संकल्पनाओं से कोई राज्य या कोई सभ्यता नहीं बनती है । लोकतंत्र किसी के निष्क्रमण पर आधारित नहीं हो सकता है । इसमें समाहित करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए क्योंकि इसमें अनेकता का तत्व होता है । इस अनेकता के तत्व को खतरे में डालना ही अतिवाद या आतंकवाद है, जो कि आज पूरे विश्व स्तर पर चल रहा है जिससे कोई भी सुरक्षित और अछूता नहीं रह सकता है । धर्म एवं दर्शन के नाम पर हिंसा और आतंक की घटनाओं को कभी-कभी वास्तव में दूसरे की सहिष्णुता पर धर्मान्धता थोपने के प्रयासों के बजाय संस्कृतियों के बीच झगड़े के रूप में दर्शाया जाता है । हमारी जैसी बहुसंस्कृति वाले देश धर्मान्धता के समर्थकों का निशाना बने रहेंगे क्योंकि हमारा समाज उनकी विचारधारा का समर्थन नहीं करता । हम भारत में भी ऐसी

ही हिंसा को झेल चुके हैं । इस शहर में भी हिंसा के निशान अभी भी हमारी स्मृति में हैं।

इस सप्ताह के प्रारंभ में, मैंने राष्ट्रपति बुश से यह कहा था कि अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद से लड़ने एवं उसे समाप्त करने में भारत किसी भी अन्य देश से पीछे नहीं है। डेढ़ दशक से भारत ने आंतकवाद के कारण अपने नागरिकों की जो जानें गंवाई हैं उसकी क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती । इससे न तो हमारा संकल्प कहीं कमजोर हुआ है और न ही हमने उन जीवन-मूल्यों को नजर अंदाज किया है, जिन पर हमारा और आपका समाज आधारित है । यह आज सबके लिए एक चुनौती बन गया है और जिस पर हम सभी मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं ।

भूमंडलीकरण - एक और चुनौती

भूमंडलीकरण एक अन्य अन्तरराष्ट्रीय विकास है जो कि हमारी विश्व-दृष्टि को प्रभावित करता है । व्यापारिक बाधाएं तेजी से खत्म हो रही हैं, विश्व आर्थिक एकीकरण ने व्यापार में विस्तार, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एवं प्रौद्योगिकी एवं व्यक्तियों के प्रवाह को प्रोत्साहित किया है । सूचना प्रौद्योगिकी के विस्फोट से ऐसे नए-नए व्यावसायिक अवसर पैदा हुए हैं जिनकी 10 वर्ष पूर्व तक कल्पना भी नहीं की जा सकती थी । अन्य विकासशील देशों की ही तरह भारत को भी इन आर्थिक अवसरों के विस्फोट से काफी अधिक लाभ मिलने की संभावना है और कई मामलों में वास्तव में उसे यह प्राप्त भी हुआ है ।

जैसा कि मैं पहले उल्लेख कर चुका हूँ, वर्ष 1991 में हमने जिन आर्थिक सुधारों की शुरूआत की थी और जिन्हें उसके बाद आने वाली सरकारों ने जारी रखा उसने एक ऐसी अर्थव्यवस्था की नींव रख दी थी जो कि भूमंडलीकरण के संभावित लाभों का दोहन कर सकती है । हमारे व्यापार में विस्तार हुआ है और हमने सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी सेवाओं जैसे कुछ क्षेत्रों में असाधारण कार्य किया है । भारत को, अब अर्थव्यवस्था संबंधी ज्ञान के क्षेत्र में मुख्य भूमिका का निर्वहन करने में सक्षम देश के रूप में देखा जाने लगा है । बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग एक ऐसा वाक्य है जिसने कई भावनात्मक मिथकों को पैदा किया है और यही इसकी क्षमता का सूचक है । भारतीय कंपनियां प्रतिदिन अमरीकी उद्यमों के लिए एक विश्वसनीय साझेदार सिद्ध हो रही हैं । समय और दूरियाँ तथा अतीत की कठिनाइयां आज के लिए लाभप्रद सिद्ध हो रही हैं । हमारे कौशल ने अमरीकी कंपनियों के प्रतिस्पर्धात्मक पहलू को अधिक तीव्र बनाने में सहायता की है ।

हालांकि भूमंडलीकरण से कई लाभ हैं परन्तु इसने एक विशेष चुनौती भी खड़ी कर दी है । किसी भी लोकतंत्र में यह आवश्यक है कि विकास की प्रक्रिया को न्यायोचित और संरक्षण के रूप में देखा जाए । विश्व में, जहां सूचना का प्रवाह निर्बाध रूप से होता है विकास की ऐसी प्रक्रियाएं व्यवहार्य नहीं होंगी जिनसे कुछ को लाभ मिले और कुछ को न मिले । किसी लोकतांत्रिक राजनीति में यह बात और भी संवेदनशील है क्योंकि इसमें जनता के असंतुष्ट हो जाने पर तत्काल चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ सकता है । भारत में हाल ही में हुए चुनावों से वस्तुतः यह संकेत मिले हैं । जैसा कि किसी ने कहा था वह सुधारों के विरोध में मतदान नहीं था । वह सुधार की प्रक्रिया के विरोध में मतदान था जिसे असंतुलित समझा गया और एक ऐसी प्रक्रिया

माना गया जिसमें ग्रामीण क्षेत्र और कृषि अर्थ- व्यवस्था की आवश्यकताओं को नजरअंदाज किया गया ।

मेरी सरकार इन समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध है । हम सुधारों को मजबूत तथा और अधिक गहन बनाएंगे जिससे भारत आज विश्व की अर्थव्यवस्था से मिलने वाले अपार अवसरों से लाभ उठा सके परन्तु हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि इन लाभों का वितरण बेहतर ढंग से हो । "सम्मिलित राजनीति" का हमारा दृष्टिकोण उदारवादी अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण पर आधारित है ।

विश्व के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था के एकीकरण से संयुक्त राज्य के साथ संभावित सहयोग के नए क्षेत्र खुलेंगे । संयुक्त राज्य सामर्थ्य की दृष्टि से मुख्य निवेशक है, परन्तु भारत में संयुक्त राज्य का निवेश अभी भी काफी कम है । हम जो विकास की दर प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए विशेष रूप से बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में भारी निवेश की आवश्यकता है, जिसका अधिकांश भाग सार्वजनिक निजी साझेदारी से आएगा । हमें विश्वास है कि संयुक्त राज्य मुक्त व्यापार की अपनी पारंपरिक प्रतिबद्धता के प्रति कटिबद्ध रहते हुए भूमंडलीकरण के लिए भारत के प्रयासों को बनाए रखने में सहायक भी हो सकता है । मैं यह स्वीकार करता हूं कि कई ऐसे मौके आए हैं जब हमने संयुक्त राज्य में संरक्षणवाद के विक्षुब्धकारी संकेत देखे हैं जो उन सभी बातों के प्रतिकूल हैं, जिनका इस देश ने समर्थन किया है । मैं कहना चाहता हूं कि इस समय जब भारत और अन्य विकासशील देशों पर भूमंडलीकरण हावी हो रहा है, मुझे आशा है कि यह बहस यहीं पर खत्म नहीं होगी । हमें संयुक्त राज्य पर भरोसा है कि वह अपने मुक्त व्यापार और उदारता के प्रति प्रतिबद्धता पर अडिग रहेगा ।

संयुक्त राज्य अमरीका में भारतीय समुदाय की भूमिका

इस देश में भारतीय अमरीकी समुदाय भविष्य में भारत संयुक्त राज्य के बीच और अधिक मजबूत सहभागिता की दृष्टि से तीसरा महत्वपूर्ण घटक है । मैं इस अवसर पर इस समुदाय की प्रशंसा करता हूँ और हमारे द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने में उनके योगदान को स्वीकार करता हूँ । भारतीय अमरीकियों ने भारत के साथ सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों के साथ निकटता बनाए रखते हुए भी अमरीकी जीवन में पूर्णतः आत्मसात होने की अपनी असाधारण विश्ष्टता को दर्शाया है । वे हमारे राष्ट्रीय हितों के बीच सेतु का कार्य करते हैं । वे हमारी युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं । भारत में उनकी क्षेत्रीय जड़ें उन्हें अलग-अलग देशों के बीच विशेष सेतु का काम करती हैं । हमें आशा है कि वे भी भारत के लिए बात करते हैं और हमारे कुछ हितों, बाधाओं और अनुभूतियों से अपने साथी अमरीकियों को अवगत कराने में सहायता करते हैं ।

भारत - संयुक्त राज्य सहयोग का वर्तमान रुझानः

मुझे इस बात की खुशी है कि पिछले पंद्रह वर्षों के दौरान हमारे द्विपक्षीय करारों में सतत विकास देखा गया है । इस प्रक्रिया की शुरूआत 1983 में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की तथा 1986 में प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की यात्रा से हुई थी । हाल के वर्षों में भारत अमरीका समीकरण का दोनों पक्षों द्वारा किए गए पुनः मूल्यांकन के उत्साहजनक परिणाम मिले हैं और इस दिशा में अभी और भी बहुत कुछ करना है ।

हाल ही में हमने "फारवर्ड लुकिंग प्रोग्राम " प्रारंभ किया है जिसके अंतर्गत नागरिक उड़ान संबंधी व्यवस्थाएं, नाभिकीय ऊर्जा, उच्च प्रौद्योगिकी वाणिज्य में

सहयोग और मिसाइल रक्षा पर वार्ता की है । ज्यों-ज्यों हम विश्वास और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे, इन क्षेत्रों में सहयोग के और अधिक व्यापक अवसर प्राप्त होंगे ।

हमारा वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी संबंधी सहयोग बढ़ा है और उसका विश्वभर में अनुप्रयोग बढ़ रहा है । उद्योग की नई संभावनाओं से इसे और अधिक बल मिला है । हमारे सहयोग के कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं - सूचना प्रौद्योगिकी, उन्नत पदार्थ अनुसंधान, औषधि और टीका (वैक्सीन) विकास ।

रक्षा के क्षेत्र में हमारे सहयोग में तीव्र वृद्धि हो रही है । हमारा आतंकवाद के विरुद्ध भी सहयोग बढ़ा है जिसके व्यापक और पुख्ता लाभ हुए हैं ।

नेपाल और श्रीलंका में संयुक्त राज्य ने लोकतांत्रिक ताकतों, सांविधानिक प्रक्रियाओं और राजनीतिक वार्ताओं को समर्थन देकर शांति और स्थायित्व को मजबूत बनाने में भारत के दृष्टिकोण का समर्थन किया है । भारत ने अफगानिस्तान में दमनकारी तालिबान शासन को हटाने और अलकायदा के आतंक को समाप्त करने के लिए संयुक्त राज्य के प्रयासों का पुरजोर समर्थन किया है । हम अफगानिस्तान की लोकतांत्रिक सरकार को राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के प्रयासों में सहायता प्रदान करने के लिए तैयार हैं ।

नई साझेदारी को पुराने उदाहरणों की जकड़न से मुक्त होना होगा । मुझे विश्वास है कि हम अपने द्विपक्षीय समझौते से आगे बढ़कर अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए वैश्विक परिदृश्य के विकास में भी सहभागी बन सकते हैं । यह उल्लेखनीय है कि

1945 का विश्व आदेश आज भी वैश्विक निर्णयों पर प्रभावी हैं । हमारे प्रमुख अन्तरराष्ट्रीय संगठनों की संरचना बीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में आए तात्कालिक राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और जनांकिकीय परिवर्तनों के प्रति पूरी तरह उन्मुक्त रही है । न केवल संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसियाँ और परिषदें पुरानी पड़ गई हैं बल्कि इसी प्रकार से बहुत से नाभिकीय प्रसार और अस्त्र नियंत्रण व्यवस्था तथा कई अन्य संधि प्रणालियां भी पुरानी पड़ गई हैं । ये सब उन खतरों से निपटने के लिए तैयार की गई थीं जो अब विद्यमान नहीं हैं या उनमें मौलिक रूप से इतना अधिक परिवर्तन हो चुका है कि उनके निष्प्रभावीकरण के लिए नए और भिन्न दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता है । मुझे विश्वास है कि वह समय आ गया है जब संयुक्त राज्य वैश्विक परिषदों में भारत का उचित स्थान देकर प्रमुख अन्तरराष्ट्रीय मुद्दों पर हमारी सहभागिता को और अधिक बढ़ाए जाने के लाभों पर गंभीरतापूर्वक विचार करे ।

भारत की भौगोलिक स्थिति और सुरक्षा परिवेश न्यूक्लियर और मिसाइल प्रौद्योगिकी के अबाधित प्रसार पर हमारी चिंता को दर्शाता है । हमारा उत्तरदायित्वपूर्ण रिकार्ड विश्व को एक सुरक्षित स्थान बनाने में संयुक्त राज्य के साथ भारत की भागीदारी के तर्क को रेखांकित करता है । इसके साथ ही हमारी सरकारें व्यापक विनाश के हथियारों और उनको लाने-ले जाने की व्यवस्था के प्रसार से उत्पन्न खतरों का समाधान कर सकती हैं । सामरिक भागीदारी के अगले कदम से जिसके प्रति राष्ट्रपति बुश और मैंने अपने-अपने देश की ओर से प्रतिबद्धता दर्शाई है, इन क्षेत्रों में हमारा सहयोग और अधिक बढ़ाएगा ।

मित्रो,

मैं आप लोगों के पास इस दृढ़ विश्वास के साथ आया हूं कि हमारे इन दोनों राष्ट्रों पर यह सुनिश्चित करने का असाधारण उत्तरदायित्व आ पड़ा है कि मानवता के इस मिलन पर दो सबसे बड़ी बुराइयों का कोई प्रभाव न पड़े, जिन्होंने पिछली शताब्दी को एक निर्दयी और हिंसा के अनिष्ट ने मानवता के प्रति सबसे अधिक बर्बर बना दिया है और चिरकाल से तथा बड़े पैमाने पर चले आ रहे अभाव के कष्ट ने ऐसे लाखों लोगों को जो प्रतिष्ठित जीवन जीना चाहते थे उससे वंचित किया है जिसके वे हकदार थे । विश्व में हिंसा और बहिष्कार - इन दो बुराइयों से बचने के लिए हमारे द्वारा किए गए प्रयासों का इतिहास साक्षी होगा ।

मुझे विश्वास है कि भारत और संयुक्त राज्य अमरीका के संबंध एक ऐसे स्तर पर पहुंच गए हैं जहां पर यह इस बड़े वैश्विक उद्देश्य की पूर्ति कर सकता है । हमारी नीतियां एक समान सिद्धांतों एवं आपसी मूल्यों पर आधारित हैं । हमारे संबंध एक परिपक्वता के स्तर तक पहुंच चुके हैं जहां पर हम अपने मतभेदों को तर्कसंगत एवं व्यावहारिक तरीके से दूर कर सकते हैं । हमारे आपसी हितों में तालमेल है तथा प्रमुख उद्देश्यों में हम एक दूसरे के पूरक हैं । यह उद्यम में स्थायी साझेदारी का ठोस आधार है, हम एक स्थायी, सुरक्षित, प्रगतिशील और न्यायसंगत विश्व व्यवस्था का निर्माण करने में लगे हुए हैं । अतः संक्षेप में मेरा संदेश सीधा-सादा है कि हम एक ही मार्ग पर चल रहे हैं और जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि अभी सर्वश्रेष्ठ परिणाम प्राप्त किया जाना है ।

धन्यवाद ।